



मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

समेकित वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली
(IFMIS) परियोजना

एक परिचय

समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS)

परिचय :-

म0प्र0 शासन वित्त विभाग अतंगत संचालनालय कोष एवं लेखा स्तर पर नवीन परियोजना 'समेकित वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (IFMIS) का विकास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित केन्द्रीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C-SFMS) परियोजना की सुविधाओं के साथ साथ अन्यानेक नवीन ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ विभिन्न विभागों, संवितरण एवं आहरण अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशनरों द्वारा उठाया जा सकेगा।

उद्देश्य :-

- वित्तीय क्रियाकलापों में पारदर्शिता बढ़ाना।
- वित्तीय प्रक्रियाओं एवं वित्त प्रबंधन में गुणात्मक सुधार।
- त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सहायता हेतु डिजीजन सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराना।
- लेखांकन प्रक्रिया को त्वरित एवं सटीक बनाना।
- कर्मचारियों/पेंशनरों/आम जनता को उपलब्ध सूचनाओं का विस्तार
- हितग्राही/भागीदारों में विश्वास की वृद्धि।

IFMIS सब-सिस्टम विवरण

1. FMIS (Financial Management Information System)
2. HRMIS (Human Resource Management Information System)
3. PMIS (Pension Management Information System)

FMIS	HRMIS	PMIS	
बजट	कर्मचारी स्वयं सेवा	पेंशन प्रबंधन	वेब पोर्टल
प्लान	सेवा संबंधी कार्य		
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट	वेतन देयक		
क्रय एवं भंडार प्रबंधन	कर्मचारी परफार्मेंस प्रबंधन		
निवेश एवं लोक ऋण प्राप्ति एवं भुगतान			
डिपोजिट			
स्ट्रांग रूम			
जनरल लेजर एवं असेट एकाउंटिंग			
आन्तरिक एवं लोकल फंड ऑडिट			

IFMIS – लाभार्थी

प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष / आहरण एवं संवितरण अधिकारी :-

- विभागवार कोषालयवार, योजनावार आय तथा बजट के विरुद्ध व्यय की स्थिति एक क्लिक पर उपलब्ध।
- प्रत्येक कार्य की प्रगति की भौतिक एवं वित्तीय ऑनलाइन जानकारी।

- डायनेमिक रिपोर्टिंग सिस्टम जिसके तहत विभागीय अधिकारी आवश्यकता अनुसार शीर्षकों पर जानकारी जनरेट कर सकेंगे।
- अनुपूरक बजट/समर्पण/बचत/पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण।
- देयकों का ऑनलाइन जनरेशन एवं कोषालय में प्रस्तुतीकरण तथा उनका स्टेटस जानने की ऑनलाइन व्यवस्था।
- भंडार/सेवाओं के क्रय की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण।

कर्मचारी :-

इंटरनेट पर घर बैठे

- सभी प्रकार के आवेदन ;विभिन्न अवकाश, विभिन्न अग्रिम सूचनाएँ, व्यक्तिगत जानकारी में सुधार सेवा निवृत्ति लाभ आदिद्व प्रस्तुत कर सकेंगे।
- सभी प्रकार के देयक ;यात्रा देयक, चिकित्सा देयक आदिद्व आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा एवं उसकी स्थिति देख सकेगा।
- सभी प्रकार की स्वीकृतियों की सूचनाएँ ;मासिक/वार्षिक वेतन स्टेटमेंट, इन्कमटेक्स रिटर्न, जी.पी.एफ, वेतन निर्धारण स्टेटमेंट, व्यक्तिगत जानकारी देख सकेगा
- सी.आर का आवेदन ऑनलाइन कर सकेगा।
- देय राशियों का खाते में सीधे भुगतान।
- स्वीकृतियों एवं भुगतान के आधार पर ई-सेवा पुस्तिका का स्वतः अपडेशन। अपनी सेवा पुस्तिका घर बैठे देख सकेगा
- कर्मचारियों के आवेदनो की ऑनलाइन स्वीकृति एवं सूचना
- सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन/ स्वीकृति /भुगतान।

पेंशनर :-

इंटरनेट पर घर बैठे

- ऑनलाइन पी.पी.ओ. हेतु आवेदन
- डुप्लीकेट पी.पी.ओ. की प्रति लेने हेतु स्वीकृति
- सभी प्रकार के आवेदन;पेंशन केस, रिवीजन, एरियर्स, सारांशिकरण, ट्रांसफर कर सकेंगे।
- सभी प्रकार की स्वीकृतियां ;पी.पी.ओ. ट्रांसफरद्व एवं जानकारियां देख सकेंगे।

नागरिक :-

इंटरनेट पर घर बैठे

- अपने टैक्स एवं शासन को देय राजस्व घर बैठे जमा कर सकेगा।
- राज्य की योजनाओं/ कार्यों की वित्तीय जानकारी घर बैठे।
- सप्लायर्स/कांट्रैक्टर्स/ हितग्राहियों/ छात्रों आदि को सीधे उनके खाते में भुगतान स्टाम्प वेंडर्स घर बैठे ऑनलाइन अपने स्टाम्प बुक करा सकेंगे।
- शासन से प्राप्त होने वाली राशियों (टैक्स रिफंड आदि) के लिए आवेदन एवं स्वीकृति तथा भुगतान प्राप्त कर सकेगा।

प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष / आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय से अपेक्षाएँ :-

- प्रत्येक कार्यालय हेतु समुचित विद्युत व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी (VPN, BB, SWAN) प्रिंटर, स्केनर, हार्डवेयर एवं विंडोज XP या अद्यतन संस्करण के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता।
- विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या में कमी करने की प्रतिबद्धता।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक कार्यालय को प्रस्तुतिकरण हेतु बायोमेट्रिक डिवाइज एवं डिजिटल हस्ताक्षर हेतु उपकरण आवश्यकता होगी।

वित्त विभाग

- राज्य की वित्तीय स्थिति की रियल टाइम मॉनीटरिंग।
- विभागवार कोषालयवार, योजनावार आय तथा बजट के विरुद्ध व्यय की स्थिति एक क्लिक पर उपलब्ध।
- व्यय पर नियंत्रण के लिए बजट का केन्द्रीयकृत नियंत्रण।
- ऑफ बजट राशियों की ऑन लाइन मॉनीटरिंग।
- बजट प्रक्रिया की ऑनलाइन तैयारी एवं बजट की किताबों का बनाना।
- शासन के निवेश एवं लोक ऋणों का ऑनलाइन प्रबंधन।
- मासिक लेखो एवं वार्षिक लेखों का ऑनलाइन जनरेशन।